

वि. सं. 1991 मन्त्रालय प्र. सं. 1081 परीक्षा सं.

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, 462004

क्रमांक एफ 4/0012/2024/सात-2

भोपाल, दिनांक 16/5/2024


प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय-मान0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित SLP (c) No. 9036-9039/2016 इंदौर डेवलेपमेंट एथोरिटी बनाम मनोहर लाल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06 मार्च 2020।

-----0000-----

विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. (सी) नं० 9036-9038/2016 इंदौर डेवलेपमेंट एथोरिटी बनाम मनोहर लाल एवं अन्य में पाँच जजों की बेंच ने दिनांक 06/03/2020 द्वारा निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 की विवेचना की गई है। मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय https://main.sci.gov.in/supremecourt/2016/8700/8700_2016_3_1501_21394_judgement_06-Mar-2020.pdf पर उपलब्ध है।


अनुभाज अधिकारी,
राजस्व (शाखा-5) विभाग
म० प्र० शासन

(राजेश कुमार कोल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

परिशिष्ट-अ (2)

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
संचालक, संचालक भवन - 405

आर.क्र./012/2135075/2024/सात-2

भोपाल, दिनांक 12.10.2024

प्रति,

फलोक्टर,
जिला - भोपाल,
मध्यप्रदेश।

विषय :- कतियासोत बांध हेतु ग्राम दागाथेहा खसरा क्रमांक 15/1, 15/2/1 की जल संसाधन विभाग के लिये अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 77/भु-अर्जन/2024, दिनांक 18.06.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का ध्यान अवलोकन करें। विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 4/0012/2024/सात-2 दिनांक 16.05.2024 की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

उक्त आदेश के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आशुद्धक एवं इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Reader to Collector Sir
12/10/24

प्र.स. 12-2024



अनुमान अधिकारी
राजस्व विभाग शाखा भोपाल

परिशिष्ट- 37(3)

क्रमांक / 270 / भू अर्जन / 2025
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/11/2025

सबीहा सुल्तान एवं अन्य परिवारजन
मुख्तारआम विमला यादव
नियामी C/O वसीस खान
भारत टाक्रीज के पीछे, मकान नं० 11, गली नं० 2,
मंगलवारा, भोपाल

विषय:- भू-अर्जन का मुआवजा भुगतान के संबंध में।
संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 17.05.2024।

--00--

विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पत्र के माध्यम से आपको द्वारा गाननीय सर्वोच्च न्यायालय की एसएलपी(सी) क्रमांक 9036-9039/2016 इंदौर डेवलपमेंट एथोरिटी बनाम मनोहर लाल एवं अन्य में पारित आदेश की कण्डिका 363(4) के तहत मुआवजा भुगतान की मांग की गई है।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सम्पूर्ण विचारण तथा कार्यालयीन अभिलेखों के परीक्षण उपरांत कलेक्टर महोदय द्वारा निर्णय लिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कण्डिका 363(4) के प्रावधान आपके प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अतः आप भू-अर्जन प्रकरण में पारित अवार्ड अनुसार वर्ष 1995 की स्थिति अनुसार प्रतिकर की निर्धारित राशि का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। कृपया मूल भू-धारक के पहचान संबंधी दस्तावेज एवं बैंक खाता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मुआवजा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। कृपया सूचित हो।

अपर कलेक्टर
जिला भोपाल

पृ.क्रमांक / भू-अर्जन / 2025
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक / / 2025

1. अवर सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर पत्र क्रमांक 1012/2135075/सात-2 दिनांक 12.09.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला भोपाल

अनुमोदित अधिकारी
राजस्व विभाग